सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-29 अंक-8 22 अप्रैल से 6 मई, 2014 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com मूल्य : 2 रुपये

महिलाओं के प्रति अपमानजनक बयान का प्रतिवाद

मुम्बई शक्ति मिल गेंगरेप के अपराधियों को फाँसी की सजा के प्रसंग में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया जिसमें उन्होंने बलात्कार जैसे संगीन अपराध को हल्के-फुल्के में लेते हुए कहा था, 'बेचारे तीन को फाँसी की सजा हो गई बम्बई में। क्या रेप में फांसी दी जायेगी? लड़के हैं, गलती हो जाती है। ऐसे कानून को बदलने की कोशिश की जायेगी।'

ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) ने इस बयान की कड़ी निन्दा की।

संगठन की महासचिव डॉ. एचजी जयालक्ष्मी ने 11 अप्रैल को जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि जब देश भर में महिलाओं से बलात्कार जैसे संगीन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, देश-विदेश में निन्दा हो रही है, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के शासक दल के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव द्वारा यह गंदा बयान दिये जाने पर हम धिक्कार देती हैं। इस बयान के जरिये उन्होंने अपने पुरुषप्रधान नजरिये से कहना चाहा है कि पुरुष गलती करते रहेंगे और महिलाएं उनका शिकार होती रहेंगी–यही दस्तूर है। इस तरह उन्होंने अपराधियों की तरफदारी करके आपराधिक कार्यों को ही बढ़ावा देने में मदद की है। संगठन की तरफ से पुरजोर मांग की गई कि केवल उन्हीं को नहीं जो बलात्कार करते हैं बल्कि उनको भी सख्त सजा दी जानी चाहिए जो जबानी तौर पर भी इस अपराध को जायज ठहराते हैं और बढ़ावा देते हैं।

दिल्ली में जंतर मंतर पर मुलायम सिंह यादव का पुतला दहन करते हुए प्रदर्शनकारी

दिल्ली :

समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के उस शर्मनाक बयान के खिलाफ यहां जंतर मंतर पर एआईएमएसएस, एआईडीवाईओ और एआईडीएसओ की दिल्ली राज्य कमेटियों के बैनर तले महिलाओं और छात्र-नौजवानों ने 12 मार्च को रोष प्रदर्शन किया। वहां हुई विरोध सभा को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल, ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की राज्य सचिव कॉ. रितु कौशिक, उपाध्यक्षों कॉ. सीता सिंह, नीतू खन्ना व पुष्पा चमोली, राज्य कमेटी सदस्य कॉ. सुमन यादव, एआईडीवाईओ दिल्ली राज्य सदस्यों प्रभाष, अमरजीत कुमार व नवीन कुमार और एआईडीएसओ दिल्ली राज्य

(शेष पृष्ठ 2 पर)

गुजरात विकास मॉडल: सच्चाई बनाम मिथ्या प्रचार

सच है कि महंगाई, घोटालों, महिलाओं पर बढ़ते अपराधों, भ्रष्टाचार, वंशगत राजनीति, अल्पसंख्यकों को धोखा देने के लिए धर्मनिरपेक्षता के झांसे के चलते कांग्रेस-नीत यूपीए बदनाम हुई है। 'नेहरू विकास मॉडल' बदनाम हो चुका है।

लेकिन 'गुजरात विकास मॉडल' कितना बढ़िया है? आइए संक्षेप में 'गुजरात विकास मॉडल' के दावों बनाम तथ्यों की पड़ताल करें। प्रत्येक शीर्षक में संदर्भ सूत्र को इटेलिक्स में दिया गया है। न्यूज रिपोर्टें मुख्यत: आई ए एन एस, पी टी आई, टाइम्स ऑफ इण्डिया, इण्डियन एक्सप्रेस, नीति सैण्ट्रल, द हिन्दू, डीएनए, अहमदाबाद मिरर से ली गई हैं।

समृद्धि और गरीबी

(गुजरात, सरकार, मोदी वेबसाइट, आरबीआई, योजना आयोग, पीआई, क्राइसिल, यूएनडीपी, न्यूज रिपोर्टें)

दावा : मि. मोदी की आर्थिक नीतियों के चलते गुजरात के लोगों की चौतरफा खुशहाली, समृद्धि और सम्पन्नता हुई है।

तथ्य : गुजरात केवल एक 'औसत दर्जे का विकसित राज्य है जो राज्यों में 12वें स्थान पर है। *(आरबीआई इण्डैक्स)*

योजना आयोग के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में गुजरात सिर्फ 11वें स्थान पर है।

गरीबी घटाने में 20 मुख्य राज्यों में से गुजरात का स्थान सिर्फ 11वाँ है। यूएनडीपी के अनुसार भारत में 5 सबसे भूखे राज्यों में गुजरात एक है। मि. मोदी के सत्तासीन होने से पहले ही गुजरात मुख्यत: शहरीकृत और आद्यौगिक राज्य था।

अपने कुल बजटीय खर्च से सामाजिक क्षेत्र पर खर्च के मामले में जो गुजरात 17 बड़े राज्यों में से 2002 में 8वें स्थान पर था वह मोदी के शासन काल में 2013 में गिरकर 15वें स्थान पर आ गया। क्राइसिल इण्डैक्स के अनुसार गुजरात समृद्धि में छठे और बराबरी में सातवें स्थान पर है।

'मोदीनोमिक्स' और 'मनमोहनोमिक्स' के बीच कोई मूलभूत अंतर नहीं है। दोनों ने ही बड़े कॉरपोरेटों की हित साधने वाली और आम जनता को मझधार में छोड़ देने वाली उन्हीं भूमण्डलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को आगे बढ़ाया है।

स्वास्थ्य

(मोदी वेबसाइट, आरबीआई, डॉ. इन्दिरा हिरवे, योजना आयोग, एनएफएचएच-3, एमएचए, सीएजी, न्यूज रिपोर्टें)

दावा : मि. मोदी ने गुजरात में स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मजबूत किया है। गरीब से गरीब का भी ध्यान रखा जाता है।

तथ्य : सन् 1999 से लेकर कुल खर्च के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य खर्च राष्ट्रीय औसत से कम रहा है।

स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति राज्य खर्च में गुजरात की स्थिति एक दशक पहले के छठे स्थान से गिरकर 2010 में 18वें स्थान पर आ गई।

2001 से 2008 तक शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में कमी राष्ट्रीय औसत से कम थी (3 पॉइण्ट तक) महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक ने बेहतर किया है।

गुजरात में, 5 वर्ष से कम का हर दूसरा बच्चा, हर तीसरी महिला और हर दूसरी किशोर लड़की वजन की कमी का शिकार थी।

देश में कुपोषण स्तर के मामले में गुजरात का स्थान बहुत ही नीचे 20वाँ है। भयंकर रूप से कुपोषित बच्चों का अनुपात यहाँ 4.56% है जो राष्ट्रीय औसत 3.33% से बहुत अधिक है।

सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता के मामले में गुजरात का स्थान 15वाँ है। गुजरात में प्रत्याशित आयु

(शेष पृष्ठ 4 पर)

एस.यू.सी.आई.(सी) स्थापना दिवस 24 अप्रैल यथोचित सम्मान के साथ मनाएं

महिलाओं के प्रति...

(पृष्ठ 1 का शेष)

अध्यक्ष कॉ. भास्करानंद व राज्य सचिव कॉ. प्रशांत कुमार, राज्य कमेटी सदस्य रवि कुमार व अन्यों ने सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने बलात्कार-विरोधी नये कानून में संशोधन करने के उनके बयान की भी कड़ी निन्दा की। कोई भी इस तथ्य को स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता कि बलात्कार के खिलाफ मौजूदा फौजदारी कानून में संशोधन इस तरह के बढ़ते अपराधों के खिलाफ देश भर में हुए ऐतिहासिक रोष प्रदर्शनों के बाद किया गया है। पुरुष, महिलाएं, समाज के जनवाद-पसंद और सद्बुद्धिसम्पन्न लोग इस कानून में बदलाव लाने की उनकी मंशा को हरगिज पूरी नहीं होने देंगे।

अंत में मुलायम सिह यादव का पुतला भी फूंका गया।

मुरादाबाद (यू.पी.) :

10 अप्रैल को मुरादाबाद के जामा मस्जिद पार्क में एक चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए उ.प्र. में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने जो अशोभनीय बयान दिया उसके खिलाफ दूसरे ही दिन अर्थात् 11 अप्रैल को मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर एआईडीवाईओ तथा एआईडीएसओ की मुरादाबाद जिला इकाइयों ने संयुक्त रूप से रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन दो घण्टे चला। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से एक खुला पत्र जिलाधिकारी, मुरादाबाद के माध्यम से श्री मुलायम सिंह यादव को भेजकर बयान वापस लेने तथा महिलाओं से माफी मांगने की मांग की गई।

रोष प्रदर्शन को मुख्य वक्ता के रूप में सम्बोधित करते हुए मुरादाबाद के प्रसिद्ध साहित्यकार व नवगीतकार डॉ. माहेश्वर तिवारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताती है लेकिन इनके इस बयान की निन्दा के लिए उनके पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई सही मानसिक संतुलन वाला व्यक्ति आज के समय में ऐसा बयान नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि आज छोटी-छोटी अबोध बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है वह मात्र एक गलती नहीं है, वह बहुत ही भयानक अपराध है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की असली जगह लोकसभा या विधानसभा नहीं बल्कि जेल है।

सभा को प्रमुख रूप से सम्बोधित करते हुए एआईडीएसओ की मुरादाबाद जिला अध्यक्षा और इस विरोध प्रदर्शन की संयोजिका कॉ. ऋतु चौधरी ने कहा कि 16 दिसम्बर के 'दामिनी' सामूहिक दुष्कर्म काण्ड के बाद भारी जन दबाव तथा जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप देश में बलात्कार के जघन्य तथा दुर्लभतम मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है ताकि इस तरह का गम्भीर अपराध करने वालों के मन में खौफ पैदा हो। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत देश में पहली बार मुम्बई की निचली अदालत ने

महिलाओं के प्रति अशोभनीय बयान पर मुरादाबाद में रोष जताते हुए एआईडीएसओ व एआईडीवाईओ कार्यकर्ता

शक्ति मिल गैंगरेप मामले में आरोपियों को बार-बार बलात्कार जैसे गम्भीर मामलों का आरोपी मानते हुए फाँसी की सजा सुनाई है। ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह यादव का उक्त बयान न केवल महिलाओं तथा छात्राओं में असुरक्षा की भावना भर देगा बल्कि इससे बलात्कारियों के हौंसले भी बुलन्द होंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को मुलायम द्वारा मुरादाबाद में दिए इस बयान की पृष्ठभूमि भी समझनी होगी। मुरादाबाद में पिछले वर्ष 13 मार्च को कक्षा 9वीं छात्रा नरगिस से स्कूल से लौटते वक्त छेड़खानी की गई तथा सरेआम उसके कपड़े फाड़ दिए गए। परिवार पुलिस-प्रशासन से गुहार लगाता रहा लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर फूल सी मासूम बच्ची ने आग लगाकर अपनी जान दे दी। हरथला काण्ड के खिलाफ मुरादाबाद में एआईडीवाईओ, एआईएमएसएस ने जोरदार आन्दोलन चलाया जिसके बाद तीनों अभियुक्त जेल गए। ये तीनों आरोपी सपा के बड़े नेताओं के बेटे हैं जो अभी भी जेल में हैं। इसके अलावा विगत 6 जुलाई 2013 को मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर वि.वि. की एमबीबीएस टॉपर छात्रा नीरज भड़ाना की हॉस्टल कैम्पस में बलात्कार के बाद नृशंस हत्या कर दी गई। इसमें टीएमयू के कुलपति सुरेश जैन व उनका पुत्र मनीष जैन मुख्य आरोपी हैं। इन्हें बचाने के लिए उ.प्र. के मुख्यमंत्री तथा उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव खुले तौर पर लगे हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए मुरादाबाद में एआईडीवाईओ, एआईडीएसओ की अगुआई में एक जोरदार आन्दोलन चल रहा है। इसी क्रम में मुरादाबाद लोकसभा से चुलाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के नाम एक 'खुला पत्र' जारी किया गया है तथा उनसे इस एमबीबीएस छात्रा के हत्यारों की गिरफ्तारी के बारे में उनका स्टैण्ड पूछा गया है। इससे सभी पार्टियाँ और प्रत्याशी परेशान हैं क्योंकि अरबपति-खरबपति इस शिक्षा माफिया सुरेश जैन से ये सभी पार्टियाँ चन्दा ले रही हैं।

मुलायम सिंह यादव ने भाषण खत्म करने के बाद दोबारा माईक पर जाकर उक्त बयान दिया। यह बयान टीएमयू काण्ड तथा हरथला काण्ड के अभियुक्तों सहित सभी अभियुक्तों को बचाने के लिए दिया गया है। यह बयान घोर निन्दनीय है। कॉ. ऋतु चौधरी ने समाज के सभी तबकों, विशेष रूप से छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुद्धिजीवियों और विवेकशील आमजनों से इस साजिश को समझने, मुलायम सिंह के बयान की कड़े शब्दों में निन्दा करने तथा विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मुँह तोड़ जवाब देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्र-युवा ही वह शक्ति है जो मुलायम सिंह को यह बयान वापस लेने के लिए मजबूर कर देगी। आज पूरे देश में तथा विशेष रूप से उ.प्र. व मुरादाबाद में महिलाओं और छात्राओं पर अपराध व बलात्कार जैसी बेइंतिहा हैवानियत की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। देखा जा रहा है कि अपराधी या तो पुलिस अथवा सत्ताधारी पार्टी से संरक्षण पाए हुए हैं। ये हालात काबिले-बर्दाश्त नहीं हैं। इसलिए महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ मजबूत जनान्दोलन आज समय की मांग है।

प्रदर्शन को एआईडीएसओ के जिला सचिव फैज खान, उपासना राजपूत, भाषा तिवारी, एआईडीवाईओ के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. हरकिशोर सिंह, कॉ. मो. गौरी, विनोद विण, ठाकुर सुरेश सिंह एडवोकेट, संध्या त्यागी, हरथला काण्ड में पीड़िता के भाई राशिद, रूबी, कमलेश चहल, कुलवंत सिंह, डॉ. इंतजार आजाद ने भी सम्बोधित किया।

इस प्रदर्शन के बाद 11 अप्रैल को मुरादाबाद के निकटवर्ती बदायूँ जनपद के बबराला की चुनावी सभा में मुलायम सिंह यादव को अपने बयान पर सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

भिवानी (हरियाणा):

समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के उस शर्मनाक बयान के खिलाफ यहां महिलाओं, छात्र-नौजवानों ने 14 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने बलात्कार जैसे संगीन अपराध को हल्के-फुल्के में लेते हुए कहा था, 'लड़के हैं, गलती हो जाती है, उन्हें फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए।' नेहरू पार्क के सामने हुई विरोध सभा को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉमरेड रामफल, जिला कमेटी सदस्य कॉ. राजकुमार और ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की कॉ. मिण्टू बाला ने सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने सभी तबके के लोगों, खासकर महिलाओं से इस महिला-विरोधी और मुजरिम-परस्त बयान का कड़ा विरोध करने का आह्वान किया।

अंत में मुलायम सिह यादव का पुतला भी फूंका गया।

महिलाओं के बारे में शर्मनाक बयान पर भिवानी में रोष जताते हुए प्रदर्शनकारी

शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को याद किया

सोनीपत (हरियाणा) : शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के 84वें बलिदान दिवस पर 23 मार्च को ऑल इण्डिया डैमोक्रेटिक स्टूडेण्ट्स ऑर्गेनाईजशन(एआईडीएसओ) व ऑल इण्डिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन(एआईडीवाईओ) की तरफ से सोनीपत की कुम्हार धर्मशाला में उनकी याद में एक सभा की गई। सभा की अध्यक्षता एआईडीवाईओ के जिला अध्यक्ष कॉ. देवेन्द्र सिंह ने की। सभा का संचालन एआईडीएसओ के विशाल दहिया ने किया।

सभा को एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी, एआईडीएसओ के जिला सचिव प्रवीण कुमार, एआईडीवाईओ के जिला अध्यक्ष कॉमरेड देवेन्द्र सिंह ने सम्बोधित किया।

21 मार्च को शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर भगवान महावीर कॉलेज ऑफ एजूकेशन, जगदीशपुर (सोनीपत) में ऑल इण्डिया डीएसओ की तरफ से आयोजित शहीदी समारोह में छात्रों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कॉलेज के सेमिनार हाल में शहीद-ए-आजम के विचारों की प्रदर्शनी व बुक स्टॉल भी लगाई गई। संगठन के जिला सचिव प्रवीण नाहरा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए भगत सिंह के जीवन-संघर्ष और उनके विचारों और अदम्य साहस जैसे गुणों पर प्रकाश डाला। कॉलेज के प्राचार्य महोदय ने भी अपनी बात रखी। ऑल इण्डिया डीवाईओ के जिला अध्यक्ष कॉमरेड देवेन्द्र सिंह ने बताया कि देश के आजादी आन्दोलन में जहाँ कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ विदेशी शोषक को भगाना था वहीं भगत सिंह का उद्देश्य था कि शोषक चाहे विदेशी हो या देशी, उखाड़ फेंको। भगत सिंह शोषणहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसके बाद 'द लैजेण्ड ऑफ भगत सिंह' फिल्म दिखाई गई।

सेमेस्टर प्रणाली ने फीस वृद्धि व शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दिया

– ऑल इण्डिया डीएसओ

भोपाल : भोपाल में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए छात्रों ने डीएसओ के नेतृत्व में सेमेस्टर सिस्टम के खिलाफ 6 मार्च को रोष प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एकत्रित होकर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए छात्र संगठन ऑल इण्डिया डीएसओ के अखिल भारतीय सचिव मण्डल सदस्य कॉ. मुदित भटनागर ने कहा कि सेमेस्टर प्रणाली के पिछले पांच वर्षों के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि सेमेस्टर प्रणाली एक छात्र-विरोधी, शिक्षा-विरोधी नीति है। इसने जहाँ एक तरफ बेतहाशा फीस वृद्धि की है वहीं दूसरी तरफ यह शिक्षा की मूल प्रक्रिया, अध्ययन-अध्यापन, पुनर्अध्ययन पर ही चोट करती है। साथ ही यह घोर अनियमितताओं व अनिश्चितताओं से परिपूर्ण है। परीक्षाओं का कोई समयांतराल तय नहीं है। सीसीई, प्रोजेक्ट, परीक्षा परिणामों में गड़बड़ियों ने इसे एकदम नकारने योग्य बना दिया है। सांस्कृतिक व खेलकूद गतिविधियों को भी नगण्य कर दिया है। इससे छात्र, प्रोफेसर व अभिभावक सभी तबके बेतहाशा परेशान हैं। अत: इस प्रणाली को तुरन्त वापस लेकर पुन: वार्षिक प्रणाली को लागू करना चाहिए तथा छात्रों, छात्र प्रतिनिधियों, प्रोफेसरों व अभिभावकों से सलाह कर सरकार को वार्षिक प्रणाली के दोषों को दूर करना चाहिए।

प्रदर्शन का संचालन अखिल भारतीय सचिव मण्डल सदस्य कॉ. सचिन जैन ने किया। प्रदर्शन को भोपाल प्रभारी विनोद लोगरिया, संगठन की ऑल इण्डिया काउंसिल की मेम्बर कॉ निवेदिता, कॉ. श्रुति शिवहरे, अजीत पंवार, योगेश धाकड़ तथा अशोकनगर से कॉ. बबीता समर, प्रमोद नामदे इन्दौर से, शाजापुर से मनोज रजाक ने सम्बोधित किया। ज्ञापन को कॉ. नित्या ने पढ़कर सुनाया।

चुनावी सरगर्मियां

जमशेदपुर (झारखण्ड) लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान चलाते हुए एसयूसीआई(कम्यूनिस्ट) के उम्मीदवार कॉमरेड सीताराम टुडु

जयनगर (प.बं.) लोकसभा क्षेत्र में वोट के लिए अपील करते हुए एसयूसीआई(कम्यूनिस्ट) के उम्मीदवार कॉमरेड तरुण मण्डल

ग्वालियर (म.प्र.) लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई(कम्यूनिस्ट) के उम्मीदवार कॉमरेड सुनील गोपाल

वडोदरा (गुजरात) लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए एसयूसीआई(कम्यूनिस्ट) के उम्मीदवार कॉमरेड तपन दासगुप्ता

गुजरात विकास मॉडल...

(पृष्ठ 1 का शेष)

सर्वोच्च स्तर वाले केरल राज्य से 7.5 वर्ष कम है और राष्ट्रीय औसत के लगभग समान है।

मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को कम करने में गुजरात से कहीं बेहतर केरल, तमिलनाडू, महाराष्ट्र हैं।

शिक्षा, कौशल विकास और साक्षरता

(गुजरात सरकार, मोदी वेबसाइट, जनगणना 2011, डीआईएसई, एमएचआरडी, एसएचईएस, एआईएसएचई, एनएसडीसी, न्यूज रिपोर्टें)

दावा : मि. मोदी का सपना एक ऐसे गुजरात का है जहाँ हर साल 100% बच्चों का दाखिला हो और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या जीरो हो और इस सपने को साकार करने के लिए सरकार जोरदार प्रयास कर रही है।

तथ्य : साक्षरता में गुजरात जो 2001 में 17वें स्थान पर था 2011 में खिसक कर 18वें स्थान पर आ गया। बिहार, यू.पी. जम्मू-कश्मीर और उड़ीसा ने कहीं बेहतर किया है।

गुजरात का प्राइमरी स्तर पर कुल दाखिला अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से कम है। इसका स्थान 22वाँ है।

गुजरात के स्कूलों में स्कूल छोड़ने वालों की दर अस्वीकार्य रूप से बहुत ऊँची 58% है जबकि राष्ट्रीय औसत 49% है।

गुजरात में प्रत्येक अध्यापक के लिए इण्टरमीडिएट स्तर पर 52 छात्र हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 34 है।

दावा : पिछले दशक में मि. मोदी के शासनकाल में गुजरात ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

तथ्य : कुल दाखिला अनुपात (उच्च शिक्षा में अध्ययनरत 18 से 23 आयु वर्ग के युवाओं का अपनी कुल आबादी का अनुपात) 17.6% है जो राष्ट्रीय औसत 20.4 से कम और तमिलनाडू से आधा है।

18 से 23 आयु वर्ग के प्रति एक लाख युवाओं के लिए गुजरात में सिर्फ 25 कॉलेज हैं जो आंध्र प्रदेश से लगभग आधा है।

गुजरात में सिर्फ 4.4% युवा ही उच्च शिक्षा में प्रवेश करते हैं। गुजरात में 1,355 वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान हैं जबकि समान जनसंख्या वाले कर्नाटक में 1,777 हैं जिनकी दाखिला क्षमता 50% अधिक है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और पूँजी अंतप्रवाह

(आरबीआई, गुजरात सरकार, मोदी वेबसाइट, एमसीए, आईआईएमबी, जीआईआरएएम/डीटीजैड)

दावा : गुजरात, एफडीआई में एक बड़े हिस्से के साथ भारत का ग्लोबल गेट वे बन गया है।

तथ्य : 2000 से 2013 के बीच भारत के एफडीआई अंतप्रवाह में गुजरात का हिस्सा मोदी शासन के दौरान सिर्फ 4% था।

एफडीआई अंतप्रवाह में गुजरात का हिस्सा विगत तीन वित्तीय वर्षों में (2011-2013) कम होता गया है।

दावा : 'खुशहाल गुजरात 2011' शिखर सम्मेलन में 20.83 लाख करोड़ रुपये का करार किया गया।

तथ्य : 'खुशहाल गुजरात 2011' शिखर सम्मेलन में करार किए गए निवेश का सिर्फ लगभग 1% ही अब तक आया है।

दावा : व्यापारिक गंतव्य स्थान के रूप में गुजरात पहली पसंद है।

तथ्य : राज्य वार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में गुजरात का स्थान सिर्फ 5वाँ है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 7.3% का योगदान करता है।

2004-2012 के बीच गुजरात के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि महाराष्ट्र, तमिलनाडू और बिहार से भी पीछे है।

दावा : मि. मोदी के शासनकाल में गुजरात पैदा ज्यादा कर रहा है और उधार कम ले रहा है।

तथ्य : भारत के तमाम प्रमुख राज्यों में से गुजरात राज्य का प्रति व्यक्ति कर्ज सबसे ज्यादा है। हर गुजराती पर 29,220 रुपये का कर्ज है।

गुजरात में जीएसडीपी और सरकारी कर्ज का अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी बदतर है 2013 में प्रति 100 रुपये उत्पादन के लिए गुजरात ने 26.1 रुपये उधार लिये हैं जबकि अन्य राज्य (औसतन) 21.9 रुपये उधार लेते हैं।

यहाँ तक कि उड़ीसा और बिहार जैसे गरीब राज्यों ने 10 सालों (2001-2011) में जीएसडीपी और सरकारी कर्ज का अनुपात कम करने में गुजरात से बेहतर काम किया है। उड़ीसा ने 51% की और बिहार ने 36% की भारी कटौती की है जिसके मुकाबले गुजरात ने मात्र 14% की कटौती की है।

दावा : देश में गुजरात अगुआ निर्यातक है।

तथ्य : निर्यात में गुजरात दूसरे नम्बर पर है (महाराष्ट्र से पीछे) और वह भी जो उत्पादन हुआ उसका 80% निर्यात करके, बहुत अधिक उत्पादन करने की वजह से नहीं।

पॉवर सेक्टर

(गुजरात सरकार, मोदी वेबसाइट, योजना आयोग, जनगणना 2011)

दावा : गुजरात एक 'एनर्जी सरप्लस' राज्य है जहाँ सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए 24 घण्टे बिजली सप्लाई रहती है।

तथ्य : रोशनी के अपने प्राथमिक स्रोत के रूप में बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों के प्रतिशत के हिसाब से भारतीय राज्यों में गुजरात का स्थान 11वाँ है। तमाम दक्षिणी राज्य जो 2001 में गुजरात से नीचे थे 2011 में गुजरात से आगे निकल गए हैं।

कृषि, घरेलू इस्तेमाल और उद्योग के लिए प्रति यूनिट औसत टैरिफ यानी बिजली रेटों के मामले में गुजरात राष्ट्रीय औसत से महंगा है और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की टैरिफ सूची में क्रमशः 17वें, 21वें और 22वें स्थान पर है।

गुजरात ने किसानों को 24 घण्टे नहीं बल्कि 10 घण्टे की बिजली सप्लाई का वायदा किया है और वह भी रात में और असमय 5-8 घण्टे दी जाती है। गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण मि. मोदी के सत्ता में आने के पहले हो चुका था।

दावा : मि. मोदी ने बिजली चोरी में कमी करवाई है और बिजली उत्पादन बढ़ाया है।

तथ्य : गुजरात में संप्रेषण और वितरण नुकसान 24% है जो अखिल भारतीय स्तर पर 15वें नम्बर पर है।

कुल इंस्टाल्ड केपेसिटी के मामले में देश में गुजरात का हिस्सा मोदी कार्यकाल के दस सालों (2001-2011) में 7.5% से घटकर 7.2% रह गया है।

मोदी शासन के 10 सालों में 2001 से 2011 के बीच सरकारी मालिकाने वाले प्लाण्टों में इंस्टाल्ड केपेसिटी 1348 मेगावॉट तक बढ़ी थी। इसी दौरान कर्नाटक ने अपनी क्षमता 2497 मेगावॉट-गुजरात से 40% ज्यादा बढ़ा ली है। इसकी क्षमता 2001 में गुजरात से कम थी जो 2011 में गुजरात से आगे निकल गया।

सड़कों का जाल

(गुजरात सरकार, मोदी वेबसाइट, योजना आयोग, आईबीएन 7, गुजरात हाई कोर्ट)

दावा : भारत में सबसे बेहतर सड़कों का जाल गुजरात में है, 90% सड़कें कोलतार की हैं।

तथ्य : गुजरात में सड़कों की लम्बाई प्रति एक लाख आबादी (80 कि.मी.) साथ ही साथ प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्र (259 कि.मी.) है जो राष्ट्रीय औसत (क्रमशः 143 कि.मी. और 388 कि.मी.) से कम है।

राज्य राजमार्गों की कुल लम्बाई के मामले में महाराष्ट्र और कर्नाटक से गुजरात कहीं पीछे है।

मि. मोदी के सत्तासीन होने के पहले ही 85% सड़कें कोलतार की थीं। बेस्ट कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आईबीएन 7 खिताब 2011 में गुजरात द्वारा जीता गया था लेकिन 2012 में पंजाब ने गुजरात को पछाड़ दिया। सड़कों की मरम्मत में भ्रष्टाचार के चलते गुजरात हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई जिसने कहा, 'अहमदाबाद में 90% सड़कों की हालत बहुत खराब है।'

श्रमिक स्थिति और रोजगार

(गुजरात सरकार, मोदी वेबसाइट, एनएसएसओ, एमएसएमई सैंसस, जेएनयू स्टडी, योजना आयोग, गुजरात एम्पलायमेण्ट एक्सचेंज, न्यूज रिपोर्टें)

दावा : गुजरात ने भारत में ज्यादा रोजगार पैदा करने और कम से कम बेरोजगारी का लक्ष्य हासिल किया है।

तथ्य : बढ़ते हुए जीएसडीपी के बावजूद भारत के उत्पादन रोजगार में गुजरात का योगदान पिछले तीन दशक (निस्संदेह मि. मोदी के दशक सहित) लगभग अवरुद्ध रहा है, इसकी वजह रही है पूँजी आधारित उत्पादन जिसमें कम रोजगारों की जरूरत होती है।

गुजरात में कुल आबादी और मजदूरों का अनुपात लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर ही है। ठेका मजदूरों का इस्तेमाल बढ़ा है जो 2001 के 19% से बढ़कर 2008 में 34% हो गया है।

8.3 लाख बेरोजगार युवाओं ने एम्पलायमेण्ट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराया है जिनमें से 6.34 लाख युवाओं ने पिछले दो सालों में नाम दर्ज कराया है यानी प्रतिदिन लगभग 1000 युवक। यदि नाम दर्ज ना कराए गए बेरोजगार लोगों को जोड़ लिया जाए तो संख्या 25-30 लाख होगी।

दावा : बाकी भारत के मुकाबले गुजराती ज्यादा कमाते हैं।

तथ्य : शहरी नियमित, ग्रामीण नियमित, शहरी कैजुअल और ग्रामीण कैजुअल-तमाम मजदूर गुजरात में राष्ट्रीय औसत से क्रमशः 13 रु., 45 रु., 25 रु., और 26 रु. कम कमाते हैं। वेतनों में धीमी बढ़ोतरी-2001-10 के दशक में मात्र 1.5% की बढ़ोतरी हुई जबकि अखिल भारतीय वेतन बढ़ोतरी 3.8% तक हुई है।

प्रति व्यक्ति आय (2012) में गुजरात 8वाँ है-एक औसत गुजराती 8 अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अपने समकक्षों से कम कमाता है।

दावा : राष्ट्रीय स्तर पर छोटे और मझोले उद्योगों का विकास 19% है जबकि गुजरात में यह क्षेत्र 85% तक बढ़ा है।

तथ्य : 2006 में 3 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ थी। अगले छः सालों में दिसम्बर 2012 तक सिर्फ लगभग 1.4 लाख इकाइयों का इजाफा हुआ है। कैसे यह 85% तक विकास कहा जाएगा?

2001-2006 के बीच लगभग 58000 इकाइयाँ (कुल इकाइयों की 20%) बंद हो गई। अकेले 2012 में गुजरात में बीमार इकाइयों की संख्या 6250 तक बढ़ गई।

महिलाओं का दर्जा

(गुजरात सरकार, मोदी वेबसाइट, जनगणना 2011, डीआईएसई, श्रम मंत्रालय, एनसीआरबी, न्यूज रिपोर्टें)

दावा : विकास के गुजरात मॉडल की 'सफलता' महिलाओं के सशक्तीकरण की वजह से है। 'कन्या केलावणी अभियान' ने बालिका शिक्षा को सुधारा है।

तथ्य : राष्ट्रीय पैमाने पर प्रत्येक 100 लड़कों के मुकाबले 94 लड़कियाँ प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश पाती हैं। गुजरात में यह सख्या 88 लड़कियों तक सीमित है।

राष्ट्रीय पैमाने पर संगठित श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी लगभग 20% है। गुजरात में पिछले एक दशक से यह दर 13% और 15% के बीच रही है।

2012 में गृहणियों द्वारा आत्महत्या के मामले में गुजरात का स्थान देश में दूसरा था।

2012 में गुजरात में लड़कियों का अनुपात (1000 लड़कों के लिए) बहुत ही कम 890 था जो राष्ट्रीय औसत 914 से कम है।

अपराध और नागरिक सुरक्षा

(गुजरात सरकार, मोदी वेबसाइट, एनसीआरबी, न्यूज रिपोर्टें)

दावा : गुजरात पुलिस ने अपराध दर को बहुत कम स्तर पर रखा है। गुजरात महिलाओं के लिए सुरक्षित है।

तथ्य : 2012 में भारत में सबसे अधिक दर्ज अपराध के मामलों की संख्या के हिसाब से गुजरात का स्थान तीसरा है।

आईपीसी अपराध दर के मामले में (प्रति एक लाख आबादी में भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज होने वाले अपराध) 216 मामलों के साथ गुजरात 195 की राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।

एसएलएल अपराध दर के मामले में (प्रति एक लाख आबादी में स्पेशल एवं लोकल कानूनों के तहत दर्ज होने वाले अपराध) 387 मामलों के साथ गुजरात 306 की राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

लोकसभा चुनावों में कर्नाटक से 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे एसयूसीआई(सी) के उम्मीदवारों को जितायें

बैंगलोर दक्षिण

इस सीट से कॉमरेड एम. उमादेवी एसयूसीआई(सी) की उम्मीदवार हैं। राजनीति शास्त्र में एम.ए, कानूनी शिक्षा में बी.ए. पास करके कॉमरेड उमादेवी ने जनआन्दोलन, क्रान्तिकारी आन्दोलन के हितार्थ खुद को समर्पित करते

हुए एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में खुद को उन्नत किया है। फिलहाल वे ऑल इण्डिया डीवाईओ की राज्य उपाध्यक्ष हैं। बहुत से युवा आन्दोलनों का उन्होंने नेतृत्व किया है। छात्रों और आम लोगों की विभिन्न मांगों के लिए आन्दोलन में वे गिरफ्तार की गई और उन्हें कारावास की सजा भी काटनी पड़ी थी। महारानी कॉलेज की छात्रा रहते हुए वे एक बार छात्र यूनियन की अध्यक्ष और एक बार महासचिव पद के लिए निर्वाचित हुई थीं। 'डोनेशन प्रथा' कैपिटेशन फीस और छात्रों की अन्य समस्याओं के खिलाफ आन्दोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भ्रष्टाचार और नारी उत्पीड़न-विरोधी तत्कालीन आन्दरोलनों में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही थी।

बैंगलोर सैण्ट्रल

इस सीट से एसयूसीआई(सी) की उम्मीदवार कॉमरेड जाहिदा शेरिन आर्ट्स और लॉ की ग्रेजुएट हैं। 1992 में किशोर अवस्था से ही वे छात्र संगठन एआईडीएसओ से जुड़ी और बहुत से आन्दोलनों का

नेतृत्व किया। छात्रों की प्रिय नेत्री के रूप में महारानी आर्ट्स कॉलेज की छात्र संसद के चुनावों में वे महासचिव चुनी गई थी। फिलहाल कॉ. शेरिन कर्नाटक राज्य की एआईएमएसएस की सचिव मण्डल सदस्य हैं। पार्टी की राजाजीनगर-विजयगर लोकल कमेटी की भी वे सदस्य हैं। नारी उत्पीड़न-विरोधी बहुत से आन्दोलनों में उनकी सक्रिय भूमिका उल्लेखनीय है।

रायचूर (एसटी)

इस सीट से एसयूसीआई(सी) उम्मीदवार कॉमरेड

के सोमशेखर 1984 में छात्र जीवन के दौरान एआईडीएसओ की संग्रामी भूमिका के प्रति आकर्षित हुए थे। इस समय से ही उन्होंने बहुत से छात्र आन्दोलनों का नेतृत्व किया है और फिलहाल एआईडीएसओ के एक राज्य स्तरीय नेता हैं। उन्होंने गुलबर्गा विश्वविद्यालय की प्रशासनिक उदासीनता, भ्रष्टाचार और परिणाम घोषित करने में अव्यवस्था के खिलाफ आन्दोलन संगठित किया। दूसरी तरफ गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के राशन कार्ड, कृषि कर्ज, परिवहन, बिजली, जल आपूर्ति इत्यादि नागरिक सेवाओं को लेकर भी उन्होंने आन्दोलन संगठित किए हैं।

कर्नाटक की 'आशा' कर्मचारियों को संगठित करके उनकी 'आशा कर्मचारी यूनियन' का गठन किया और वे इस संगठन के राज्य अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वे मजदूर संगठन एआईयूटीयूसी की राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष हैं।

धारवाड़

इस सीट से पार्टी के उम्मीदवार कॉमरेड गंगाधर

बादीगर ने छात्र संगठन एआईडीएसओ के माध्यम से राजनैतिक जीवन में प्रवेश किया। फिलहाल वे एआईडीएसओ के राज्य उपाध्यक्ष हैं। आशा कर्मचारी यूनियन के वे जिला अध्यक्ष हैं। ऑल इण्डिया सेव एजूकेशन कमेटी की राज्य शाखा के वे सदस्य हैं।

गुलबर्गा (एसटी)

इस सीट से पार्टी उम्मीदार कॉमरेड एसएस शर्मा

छात्र- युवा- महिला और आम लोगों सहित सभी तबकों के लोगों की विभिन्न जनवादी मांगों को लेकर होने वाले आन्दोलनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। नर्सिंग कॉलेज बन्द करने के खिलाफ, विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि, हॉस्टल में प्रशासनिक अव्यवस्था के खिलाफ, सड़क चौड़ी करने के नाम पर गरीब लोगों को उजाड़ने के खिलाफ भी गुलबर्गा में उन्होंने आन्दोलन किए हैं। स्वच्छ पीने के पानी, महिला कॉलेज की मांग पर और जल आपूर्ति व्यवस्था के निजीकरण करने की परिकल्पना के प्रतिवाद में आन्दोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

बेल्लारी

इस सीट से एसयूसीआई(सी) के उम्मीदवार कॉ. ए देवदास फिलहाल जिला कृषक संगठन आरकेएस के अध्यक्ष हैं और मजदूर संगठन एआईयूटीयूसी के वे राज्य स्तर के एक नेता हैं। खदान मजदूरों और निर्माण मजदूरों के आन्दोलन का उन्होंने नेतृत्व किया है। हाल की बाढ़ में बेल्लारी अंचल में राहत कार्यों में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट पर आजाद उम्मीदवार ने एसयूसीआई(सी) उम्मीदवार के समर्थन में अपना नाम वापस लिया

धारवाड़ लोकसभा सीट से प्रजारंगा (एक प्रगतिशील संगठन) समर्थित आजाद उम्मीदवार विकास बी. सोप्पाना ने एसयूसीआई(सी) उम्मीदवार गंगाधर बादीगर के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया। सन्मति रोड धारवाड़ स्थित एसयूसीआई (सी) कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इसका ऐलान किया गया। संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री विकास बी. सोप्पाना ने कहा, ''मैं एसयूसीआई(सी) उम्मीदवार श्री गंगाधर बादीगर के समर्थन में अपना नाम वापस लेता हूँ क्योंकि हमारा प्लेटफार्म जनआन्दोलनों के निर्माण में यकीन रखता है। क्योंकि एसयूसीआई(सी) दशकों से जनआन्दोलनों का निर्माण कर रही है और समय की मांग है कि तमाम जन-परस्त संघर्षशील लोग एक हो जाएं और तमाम जातिवादी और साम्प्रदायिक राष्ट्रीय पार्टियों को परास्त करें। मैं तहेदिल से गंगाधर बादीगर का समर्थन करता हूँ। मैं अपने तमाम अनुयायिओं और समर्थकों के साथ-साथ आम जनता से भी आह्वान करता हूँ कि अन्य राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टियों के झूठे वायदों के झांसे में न आ कर उनको वोट दें और प्रचार के बाकी बचे हुए दिनों में उनके लिए काम करें।''

एसयूसीआई(सी) धारवाड़ जिला सचिव कॉमरेड रमनजनप्पा अल्दाल्ली और एसयूसीआई(सी) उम्मीदवार गंगाधर बादीगर भी इस अवसर पर मौजूद थे। इसके अलावा सीटू और डीवाईएफआई के पूर्व नेतागण जो कॉमरेड सोपिन के साथ आए थे वे भी उपस्थित थे।

डीएसओ-डीवाईओ का राजनैतिक शिक्षण शिविर

सुल्तानपुर (उ.प्र.) में 3-4 मार्च को एआईडीएसओ- और एआईडीवाईओ के राजनैतिक शिक्षण शिविर का संचालन करते हुए एसयूसीआई(कम्यूनिस्ट) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रंजीत धर।

आंध्र प्रदेश में लोकसभा व विधान सभा चुनावों में एसयूसीआई(सी) प्रत्याशियों को विजयी बनायें

आन्ध्र प्रदेश में दो संसदीय सीटों पर एसयूसीआई(सी) उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं

सिकन्दराबाद संसदीय क्षेत्र से सीएच मुराहारी

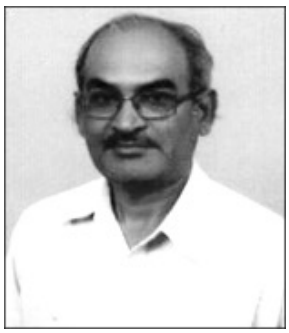

कॉमरेड सीएच मुराहारी एसयूसीआई(सी) आन्ध्र प्रदेश राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य हैं और हैदराबाद जिला सांगठनिक कमेटी के सचिव हैं। आप पीपुल्स कमेटी फॉर सेफ एनर्जी (पीसीओएसई), आन्ध्र प्रदेश के इंचार्ज और ऑल इण्डिया एण्टी एम्पीरियलिस्ट फोरम, आन्ध्र प्रदेश के सचिव हैं।

आन्दोलनों में हिस्सेदारी या नेतृत्व: पार्टी और अन्य संगठनों द्वारा संचालित आन्दोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई है। हैदराबाद में कई साम्राज्यवाद-विरोधी, युद्ध-विरोधी प्रतिवादों और रैलियों को नेतृत्व प्रदान किया। इनमें उल्लेखनीय है हैदराबाद में अन्य वाम पार्टियों के साथ मिलकर किया गया ''क्लिण्टन वापस जाओ'' प्रतिवाद प्रदर्शन।

दूसरा उल्लेखनीय आन्दोलन था 2000 में आंध्र प्रदेश में अन्य वाम पार्टियों के साथ मिल कर किया गया बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ आन्दोलन। तीन महीने लम्बे चले इस आन्दोलन की वजह से तत्कालीन शासक पार्टी तेलगू देशम पार्टी इतनी अलोकप्रिय हो गई कि अगले चुनावों में सरकारी गद्दी से बाहर हो गई।

अनन्तपुर संसदीय क्षेत्र से जी ललिता

कॉमरेड जी. ललिता एसयूसीआई(सी) की राज्य सांगठनिक कमेटी की सदस्य और ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की राज्याध्यक्षा हैं। कॉमरेड ललिता अण्डरग्राऊण्ड ड्रेनेज साधना कमेटी की सचिव और नम्बुला पुलाकुंता यूरेनियम प्लांण्ट के खिलाफ संघर्ष कमेटी की सचिव हैं।

पार्टी और एआईएमएसएस द्वारा संचालित अनेक आन्दोलनों में आपकी भागीदारी रही है। इनमें उल्लेखनीय हैं: मीडिया में अश्लीलता के खिलाफ आन्दोलन, राज्य के बंटवारे के खिलाफ आन्दोलन, नम्बुलापुलकुता में विनाशकारी यूरेनियम प्लाण्ट के खिलाफ संघर्ष, महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ, विशेषकर 'निर्भया' केस में अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए आन्दोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन, अनन्तपुर शहर में अण्डरग्राऊण्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए 231 करोड़ रुपये की मंजूरी के लिए एक सफल आन्दोलन। अनन्तपुर और हिन्दूपुर में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के आन्दोलन के सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

चार विधानसभा क्षेत्रों से भी पार्टी चुनाव लड़ रही है।

विशाखापट्टनम पूर्व विधानसभा क्षेत्र से गोविन्दराजलू

कॉमरेड गोविन्दराजलू एसयूसीआई (सी) राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य और विशाखाट्टनम पार्टी यूनिट के इंचार्ज हैं। आप ऑल इण्डिया सेव एजूकेशन कमेटी के स्टेट इंचार्ज और बाल विकास वैदिका (बच्चों के समग्र विकास के लिए एक फोरम) के संयोजक हैं।

आन्दोलनों में भागीदारी या नेतृत्व : पार्टी, एआईडीएसओ और जनकमेटियों द्वारा संचालित अनेक आन्दोलनों का नेतृत्व किया। उनमें से उल्लेखनीय हैं : इण्टरमीडिएट छात्रों की परीक्षा फीस वृद्धि और केपीटेशन फीस आधारित निजी मेडिकल-डेण्टल कॉलेज खोलने के खिलाफ आन्दोलन, वोकेशनल छात्रों का आन्दोलन, आईटीआई छात्रों की ज्वलंत समस्याओं पर दीर्घकालिक आन्दोलन, विभिन्न सरकारी विभागों में दो लाख रिक्त पदों को भरने के लिए आन्दोलन, यौन शिक्षा पर संसदीय स्थाई समिति की मीटिंग के दौरान विरोध प्रदर्शन। तमाम प्राइवेट स्कूलों में भारी फीस वृद्धि के खिलाफ सफल आन्दोलन, हैदराबाद में नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल प्रबन्धन और विशाखापट्टनम में डीडीआर नर्सिंग स्कूल में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन, पोलीटैक्निक छात्रों की मांगों पर एक राज्य स्तरीय आन्दोलन संगठित किया गया। संयुक्त आंध्र प्रदेश के लिए और क्षेत्रीयतावाद के खिलाफ आन्दोलन, महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ आन्दोलन, विशेषकर 'निर्भया' केस में अपराधियों को सजा दिलवाने और अन्ना हजारे के आन्दोलन के अवसर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन।

खैराताबाद विधान सभा क्षेत्र से ई. हेमलता

कॉमरेड ई. हेमलता एसयूसीआई(सी) की लोकल सांगठनिक कमेटी की सदस्य हैं और एआईएमएसएस की हैदराबाद जिला कमेटी की अध्यक्षा हैं।

आपने पार्टी और एआईएमएसएस द्वारा संचालित अनेक आन्दोलनों में भागीदारी की है। उनमें से कुछ ये हैं : इण्टरमीडिएट फीस वृद्धि के खिलाफ एक आन्दोलन, नाईटिंगेल नर्सिंग स्कूल मैनेजमैण्ट के भ्रष्ट कृत्यों के खिलाफ सफल आन्दोलन, अन्ना हजारे आन्दोलन के अवसर पर भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन। महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ संगठित सभी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इनमें से उल्लेखनीय है 'निर्भया' आन्दोलन जो आज भी विभिन्न रूपों में जारी है।

अनन्तपुर (शहरी) विधानसभा क्षेत्र से डी राघवेन्द्र

कॉमरेड डी राघवेन्द्र एसयूसीआई (सी) की अनन्तपुर लोकल सांगठनिक कमेटी के सचिव हैं और एआईडीएसओ के राज्य अध्यक्ष हैं।

आपने पार्टी और एआईडीएसओ द्वारा संचालित अनेक जनआन्दोलनों में शिरकत की और नेतृत्व प्रदान किया। इनमें उल्लेखनीय हैं: राज्य के बंटवारे के खिलाफ आन्दोलन, नाम्बुला पुलाकुता में विनाशकारी यूरेनियम प्लाण्ट के खिलाफ आन्दोलन, महिलाओं पर अत्याचारों और अपराध के खिलाफ, विशेषकर 'निर्भया' केस के अपराधियों को सजा दिलाने का आन्दोलन, अन्ना हजारे द्वारा शुरू किया गया भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन, अनन्तपुर शहर में अण्डर ग्राऊण्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए सफल आन्दोलन, पोलीटैक्निक छात्रों का सफल आन्दोलन। अनन्तपुर और हिन्दूपुर में भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी। राहत कार्यों के प्रोग्रामों में शिरकत की, मेडिकल कैम्प लगाए और गरीब लोगों के लिए स्कूल चलाये।

हिन्दूपुर विधान सभा क्षेत्र से राम बासवराजू

कॉमरेड राम बासवराजू एसयूसीआई(सी) की हिन्दूपुर लोकल सांगठनिक कमेटी के सदस्य हैं और एआईडीएसओ के राज्य कोषाध्यक्ष हैं।

आपने पार्टी और एआईडीएसओ द्वारा संचालित अनेक आन्दोलनों में हिस्सा लिया। इनमें से मुख्य हैं : सरकारी जूनियर कॉलेज स्थापित करने के लिए आन्दोलन, नेत्रहीन छात्राओं की मर्यादा के लिए आन्दोलन जिनका उनके अपने ही कैम्पस में यौन उत्पीड़न किया गया था, आईटीआई, पोलीटैक्निक छात्रों की मांगों को लेकर आन्दोलन, हिन्दूपुर के लिए पीने का पानी मुहैया कराने का आन्दोलन और रेशम बुनकरों का संघर्ष। हिन्दूपुर में भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के संघर्ष में सक्रिय भागीदारी।

चुनावी सरगर्मियां

बिहार के बांका लोकसभा क्षेत्र से नामांकन के लिए जाते हुए एसयूसीआई(सी) के उम्मीदवार

ओडिशा में रोड शो करते हुए लोकसभा सीट के एसयूसीआई(सी) के उम्मीदवार

आन्ध्र प्रदेश के सिकन्दराबाद लोकसभा क्षेत्र से एसयूसीआई(सी) के उम्मीदवार सीएच मुराहारी

झारखण्ड के जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से एसयूसीआई(सी) के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में कॉ. छाया मुखर्जी

गुजरात विकास मॉडल...

(पृष्ठ 4 का शेष)

खुद गृह मंत्री सहित 32 बीजेपी एमएलए आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

महिलाओं के खिलाफ हर तरह के अपराधों के लिए पहले से ही कम राष्ट्रीय सजा दर से गुजरात की सजा दर बहुत ही कम हैं–दहेज हत्याओं में 0%, घरेलू हिंसा, आक्रमण, अपहरण और अगुआ करने के मामलों में 10% से भी कम है।

पानी, सिंचाई, और कृषि

(गुजरात सरकार, मोदी वेबसाइट, आईडब्ल्यूएमआई/ आईएफपीआरआई, आईआरएपी, नाबार्ड, एनएसएसओ, कृषि मंत्रालय, न्यूज रिपोर्टें)

दावा : नर्मदा प्रोजेक्टों की बदौलत लम्बी दूरियों के लिए पाइपों से जल आपूर्ति की जा रही है।

तथ्य : पिछली गर्मियों (2012) में गुजरात ने भयंकर सूखे का सामना किया जिसने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों को सुखा दिया था, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4000 गाँवों और कस्बों में पानी की भारी किल्लत हो गई थी।

सरदार सरोवर परियोजना की नहरों के नेटवर्क का 75% काम अभी भी पूरा होना बाकी है।

दावा : कृषि में असाधारण वृद्धि हुई है। 2001-2007 के बीच कृषि में सकल राज्य घरेलू उत्पादन(जीएसडीपी) प्रतिवर्ष 9.6% तक बढ़ा और 10% विकास गाथा जारी है।

तथ्य : यह वृद्धि नहीं थी बल्कि 4 बढ़िया मानसूनों की वजह से 1999-2000 के सूखे से रिकवरी थी। 10% वृद्धि मि. मोदी से पहले थी (आईआरएपी स्टडी) 2008 और 2012 के बीच कृषि दर असल में सिर्फ 4.8% तक नीचे आ गई (कृषि मंत्रालय)

यहाँ तक कि गुजरात सरकार के स्रोत बताते हैं कि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में जीएसडीपी की वृद्धि दर 2006-2011 के बीच मात्र 3.44% रही।

2011 के मुकाबले वर्ष 2012 में खाद्यान्न उत्पादन 8 लाख टन तक घट गया।

सिंचाई योग्य भूमि के सिर्फ 36% में ही असल में सिंचाई हुई। यह 40% की राष्ट्रीय औसत से कम है। हर 5 एकड़ में से 4 एकड़ की सिंचाई कुओं और ट्यूबवेलों से होती है बड़े डेमों से नहीं। अतः, उत्पादन मात्रा अस्थिर है।

गुजरात में उत्पादकता की वृद्धि दर 1991-2000 में 4.7% थी वह अगले दशक 2001-2011 में घट कर 3. 4% रह गई। झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि उड़ीसा ने भी इससे अच्छा प्रदर्शन किया है।

कृषि के कॉरपोरेटाइजेशन की वजह से 2005 से 2010 तक रोजगार 1.6% तक कम हो गए।

भ्रष्टाचार

(गुजरात सरकार, मोदी वेबसाइट, न्यूज रिपोर्टें)

दावा : गुजरात में भ्रष्टाचार मृत्यु शैया पर है और उभरने का कोई मौका नहीं है।

तथ्य : जब से मि. मोदी सत्तासीन हुए हैं गुजरात में लोकायुक्त नहीं है। गैरकानूनी खनन के मामले में एक वरिष्ठ मंत्री को तीन साल की कैद हुई लेकिन वे मंत्री बने रहे।

राज्यपाल या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना मनमाने ढंग से हाल ही में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी।

प्रशासन और राज काज

(गुजरात सरकार, मोदी वेबसाइट, लीक हुआ केबिनेट नोट, आर.के. मिश्रा, सीएजी, न्यूज रिपोर्टें)

दावा : गुजरात सरकार ने राज्य संचालित सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में 'प्रोफेशनलिज़्म' लागू किया है। मि.मोदी 'बिजनेस फ्रेण्डली' मुख्यमंत्री हैं।

तथ्य : 2012 में सीएजी रिपोर्ट में राज्य उद्यमों द्वारा की गई 16,700 करोड़ रुपये की अनियमितताएं दर्ज की गई हैं। इनमें कोरपोरेट घरानों को नाजायज फायदा पहुँचाया गया है जिसका परिमाण 2011 में हुई अनियमितताओं से 4 गुना अधिक है। सीएजी ने अधिक प्रोफेशनलिज़्म और जवाबदेही के लिए कहा है।

मि. मोदी वाकई में 'बिग बिजनैस फ्रेण्डली' मुख्यमंत्री हैं। नेनो कार के लिए टाटा को दी गई रियायतों और सुविधाओं का रुपयों में आंकलन करें तो यह 30,000 करोड़ रुपए बैठता है। 2000 में अदानी समूह 3000 करोड़ रुपये का मालिक था लेकिन 2013 में यह 47,000 करोड़ रुपये के साम्राज्य का स्वामी बन गया। वजह रही सस्ती भूमि दरें, उससे बिजली खरीदने की अत्यंत महंगी दरें, प्लम इंफ्रा डील्स और अन्य मेहरबानियाँ। अन्य फायदा उठाने वालों में शामिल हैं रिलायंस, एस्सार, एल एण्ड टी, रहेजा, सीएलपी इत्यादि।

मि. मोदी की लोकप्रियता

(खबरें, मोदी वेबसाइट, स्टेटसपीपल डॉट कॉम और राजनीतिक विश्लेषण)

दावा : मि. मोदी ने लगातार तीन चुनाव जीते।

तथ्य : मि. ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। माणिक सरकार त्रिपुरा में लगातार चार बार चुनाव जीते। तरुण गोगोई (असम) शिवराज चौहान (म.प्र.) शीला दीक्षित (दिल्ली), रमण सिंह (छत्तीस गढ़) ने हैट ट्रिक बनाई थी। मि. मोदी के अलावा माधव सिंह सोलंकी (गुजरात) 4 कार्यकालों के लिए मुख्यमंत्री रहे।

दावा : हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में *'मोदी लहर'* की वजह से बीजेपी की जीत हुई।

तथ्य : दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर आम आदमी पार्टी के चलते 2008 के मुकाबले 3% से भी अधिक नीचे आ गया। मि. मोदी ने 6 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों की थी इनमें से सिर्फ दो में बीजेपी उम्मीदवार जीत पाये। छत्तीसगढ़ में 2008 के मुकाबले बीजेपी की एक सीट घट गई, 12 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 सीटें बीजेपी द्वारा गवां दी गई जहाँ मि. मोदी ने प्रचार किया था। कांगेस के मतों में 1% इजाफा हुआ।

मध्य प्रदेश में खुद बीजेपी में ही जीत का श्रेय मोदी को देने पर भारी मतभेद है। एल के आडवाणी और शिवराज चौहान दोनों ही अनिच्छुक हैं।

राजस्थान में कांग्रेस विरोधी लहर थी। 6 लाख से अधिक वोटरों ने नोटा का बटन दबाया जो चारों राज्यों में सबसे अधिक है। मोदी प्रचार ने दोयम भूमिका निभाई।

दावा : मि. मोदी नेटीजनों के बीच लोकप्रिय हैं।

तथ्य : अक्टूबर 2013 में मोदी के ट्वीटर फोलोवरों के बीच 76% फेक, 18% निष्क्रिय और सिर्फ 6% असल यूजर थे। लेकिन बीजेपी ने सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करने का प्रयास कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से बेहतर किया है।

मि. मोदी के तहत मीडिया की भूमिका और आजादी

(गुजरात सरकार, मोदी वेबसाइट, न्यूज रिपोर्टें)

दावा : मीडिया मोदी के खिलाफ पक्षपातपूर्ण है, झूठ फैला रहा है।

तथ्य : मि. मोदी पर पत्रकारों द्वारा की जाने वाली तीखी टिप्पणियों के लिए पत्रकारों को प्रबंधकों के कोप का भाजन होना पड़ा रहा है।

सन टीवी के एक एंकर, द हिन्दू के एडिटरों, ओपन, नेटवर्क 18, ट्विटर मि. मोदी के प्रति तल्ख होने की वजह से हटा दिए गए।

खबरों में मोदी-परस्त प्रचार छाया हुआ है।

टीवी चैनल (जैसे सीएनएन-आईबीएन 7, टाइम्स नाऊ) मोदी को अधिकाधिक बढ़चढ़ कर और सक्रिय तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ताजा खबर है कि इण्डिया टीवी पर रजत शर्मा के कार्यक्रम ''आपकी अदालत'' में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के चले 'फिक्सड' 'स्टेजड इंटरव्यू' के विरोध में इण्डिया टीवी के एडिटोरियल डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने इस्तीफा दिया है।

दावा : मि. मोदी के गुजरात में आजादी और जनतंत्र है।

तथ्य : गुजरात में कलाकार और लेखक डर के साए में रहते हैं। बौद्धिक स्वतंत्रता को दबाया जाता है। *(गुहा, दि टेलिग्राफ, 22 मार्च, 2014)*

गुजरात आईपीएस अधिकारीगण, आर बी, श्री कुमार, कुलदीप शर्मा, संजीव भट्ट, रजनीश राय और आईएएस अफसर राहुल शर्मा को 'हद पार' करने के लिए प्रताड़ित किया गया। यहाँ तक कि मोदी परस्त आईपीएस अफसर डीजी बंजारा को भी नहीं बख्शा गया।

रिलायंस टैक्सटाइल, अपोलो टायर्स और बम्बार्डियर ट्रांस्पोर्टेशन पर हुए मजदूर प्रदर्शनों को गैर कानूनी घोषित किया गया।

जैसा कि उनके जिन अपने पार्टी सहयोगियों, पत्रकारों और विदेशी राजनायिकों ने उनको निकट से देखा है उन्होंने स्वीकार किया है कि मि. मोदी की कार्यशैली तानाशाहीपूर्ण है। वे कोई आलोचना नहीं सुनते, अपने ही मद में चूर रहते हैं और अपने खुद के मंत्रियों को भी दरकिनार कर देते हैं। वह संकीर्णमना, अविश्वासी व्यक्ति, सत्ता को मुट्ठी में रखने वाला और भय व संत्रास के बल पर शासन करता है।

अंततः, गुजरात का विकास मॉडल

(गुजरात सरकार, मोदी वेबसाइट, अर्थशास्त्रियों के विचार (अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, मैत्रीश घटक, इन्दिरा हिरवे)

दावा : गुजरात का विकास मॉडल निवेश के लिए परिवेश तैयार करता है, उत्पादन बढ़ाता है, हर एक के लिए जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है।

तथ्य : मि. मोदी के शासनकाल में गुजरात में ऐसे किसी मूलतः भिन्न विकास का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। 2001-10 के दशक में इसका परफोरमेंस मोदी के आर्थिक नेतृत्व के बारे में ऐसे किसी सनकी हर्षोन्माद और उल्लासपूर्ण अति आशावाद को जायज नहीं ठहराता है।

कारपोरेट घरानों के लिए मि. मोदी बहुत चहेते हैं, उन्होंने खजाने को खाली करते हुए मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ नागरिक और ढांचागत सुविधाएं प्रदान की हैं। लेकिन ऐसा करते हुए गरीबों और हाशिए पर धकेल दिए लोगों को अपने विकास एजेण्डे से पूरी तरह बाहर कर दिया है। संक्षेप में यह है 'गुजरात का विकास मॉडल'।

वडोदरा में छात्रों का रोष प्रदर्शन

'कॉलेज में छात्रों के ऑनलाइन दाखिलों को अनिवार्य करना नहीं चलेगा' – इस मांग को लेकर गुजरात के वडोदरा में एम एस विश्वविद्यालय में एआईडीएसओ के नेतृत्व में छात्रों ने रोष प्रदर्शन किया। गत शैक्षणिक वर्ष के शुरूआत में विश्वविद्यालय अथोरिटियों की ओर से पहली बार ऑनलाइन दाखिलों की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने के फैसले का ऐलान किया गया तभी से एआईडीएसओ आन्दोलन चलाता आया है। गत एक वर्ष में इस दाखिला प्रक्रिया के कारण छात्र-छात्राओं का काफी दिक्कतों से पाला पड़ रहा है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अथोरिटियों ने इस बार दाखिला फीस भी बढ़ा दी है। फीस बढ़ोतरी को वापिस लेने की मांग भी एआईडीएसओ के आन्दोलन की एक मांग है। परीक्षाएं चलने के बावजूद छात्र-छात्राएं प्रबल उत्साह के साथ इस रोष प्रदर्शन में शामिल हुए।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Printing : 20 April, 2014

मई दिवस शानदार ढंग से मनायें

मई दिवस नजदीक आ रहा है। पहली मई को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। मई दिवस हर तरह के शोषण–अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है, अपने हकों व न्याय के लिये आवाज बुलन्द करने का दिन है, अपनी मांगों के लिये दुनिया के मजदूरों के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करने का दिन है, पूंजीवादी शोषण–जुल्म के जाल को तोड़ फेंकने के लिए एकताबद्ध संघर्ष का दृढ़ संकल्प लेने का दिन है। इस दिन कारखानों, खेतों व खदानों के मजदूर, चिनाई मजदूर–मिस्त्री, बैंक–बीमा–रेल–बन्दरगाह–डाकघर–टेलीफोन के कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर व हैल्पर आदि सभी मजदूर–कर्मचारी अपनी एकता व भाईचारे को मजबूत करने के लिये इकट्ठा होते हैं। मजदूर आन्दोलन पहली मई 1886 से लेकर आज तक अनेक उतार–चढ़ाव देख चुका है। हमें उन सब से सबक लेना है।

मई दिवस का इतिहास

मई दिवस का इतिहास वीरतापूर्ण संघर्षों व कुर्बानियों का गौरवशाली इतिहास है। 19वीं शताब्दी में यूरोप व अमेरिका के कारखानेदार और उनकी ताबेदार सरकार बातें तो न्याय, बराबरी, आजादी व जनतन्त्र की करते थे मगर मजदूरों व अन्य शोषित–पीड़ित मेहनतकशों से बर्ताव गुलामों जैसा किया करते थे। उनको रोजाना 12 घण्टे से भी ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करते थे। इसके खिलाफ मजदूरों ने देश–देश में 8 घण्टे के कार्य–दिवस की मांग उठाई। इस मांग को लेकर 1856 में आस्ट्रेलिया में पहली हड़ताल हुई। दूसरी हड़ताल 1862 में भारत में हावड़ा के 1200 रेलवे मजदूरों ने की। 1886 में 1 मई को अमेरिका में भी 8 घण्टे का कार्यदिवस करने की मांग पर सफल हड़ताल हुई। इससे पूंजीपति वर्ग बौखला उठा और पहली मई को जब शिकागो शहर के हे–मार्केट चौक में मजदूर शान्तिपूर्ण सभा कर रहे थे तब उन पर पुलिसिया दमन चक्र चलाया गया। मजदूरों के बहे खून से झण्डा लाल हो गया। कई मजदूर घायल हुये, बहुत सारे गिरफ्तार कर लिए गये। झूठे केस बनाकर 4 मजदूर नेताओं को फांसी की सजा दी गई। इस घटना ने अमेरिका में 'जनतंत्र' व 'आजादी' के लम्बे चौड़े दावों की पोल खोल दी। इस घटना ने उसके शासक–शोषक वर्ग और उनकी राजसत्ता के क्रूर व घिनौने चेहरे से नकाब हटा दिया। जिस अमेरिका को धरती पर पूंजीवादी 'स्वर्ग' कहा जाता था उसके बारे में इसने लोगों में व्याप्त भ्रम दूर कर दिया। यह कोशिश मजदूर वर्ग के व्यापक राजनैतिक संघर्ष के एक नये स्तर का प्रतीक थी। 8 घण्टे के कार्य दिवस की साझी माँग पर मजदूर वर्ग की विभिन्न पार्टियों, मजदूर संगठनों और लेबर यूनियनों के एकजुट संघर्ष के प्रतीक के रूप में यह दिन उभर कर आया।

विश्व सर्वहारा के क्रान्तिकारी आन्दोलन के महान् नेता, शिक्षक व पथ–प्रदर्शक फ्रेडरिक एंगेल्स के आह्वान पर 1890 से पहली मई का दिन सारी दुनिया में मजदूर–दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मई दिवस का महत्व दर्शाते हुए उन्होंने कहा था कि, ''एक तरफ दुनियाभर के सर्वहारा–मजदूरों का खेमा है जो सर्वत्र मुक्ति के परचम तले जीत की तरफ लम्बे डग भर रहा है, दूसरी तरफ अपनी शोषणमूलक सुविधाओं–विशेषाधिकारों को बचाने के लिए पूंजीपतियों, धनवानों व प्रतिक्रियावादियों ने हाथ मिला लिये हैं। इन दोनों खेमों के बीच संघर्ष शुरू हो चुका है...जीत आपकी होगी–आगे बढ़ो।'' इतिहास गवाह है कि तमाम दमन–उत्पीड़न के बावजूद मजदूर आन्दोलन आगे बढ़ा और भारत समेत हर देश में 8 घण्टे के कार्य दिवस को कानूनी मान्यता मिली। याद रहे, मजदूर–कर्मचारियों के हक में जितने भी कानून बने हैं वे सभी हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों के फल हैं।

सभी समस्याओं की जड़ है पूंजीवाद

मालिक और मजदूर इन दो वर्गों में विभाजित समाज में इन दोनों वर्गों के हित न केवल अलग–अलग हैं बल्कि एक–दूसरे के विपरीत भी हैं। मजदूर अपनी श्रमशक्ति बेचता है और मालिक पूंजीपति इसे खरीदता है। मजदूरों का खून चूस कर पूंजीपति अपने मुनाफे के अम्बार लगाते जाते हैं। इस निर्मम लूट के चलते मेहनतकश जनता की खरीद शक्ति घटती जाने से बाजार घटता जा रहा है। आज विश्व पैमाने पर पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था भारी मन्दी में फंस गई है और इसके संकट का सारा बोझ मजदूर–कर्मचारियों, किसानों व अन्य मेहनतकशों पर डाला जा रहा है। शोषणमूलक पूंजीवादी शोषण के चलते अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी गरीब। इस मरणासन्न विश्व–पूंजीवाद का अभिन्न अंग होने के चलते हमारे देश में पूंजीवाद संकटग्रस्त है। यहां भी लोगों की दशा कोई बेहतर नहीं है। शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था को मंदी के संकट से उबारने के लिए 1991 में लाया गया पूंजीवादी भूमण्डलीकरण–निजीकरण का नुस्खा भी काम नहीं आया। इन नीतियों के चलते महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मजदूर–कर्मचारियों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। लाखों खाली पड़े पद भरे नहीं जा रहे हैं। नई भर्ती पर रोक है। पीपीपी के नाम पर सेवा क्षेत्र का निजीकरण–व्यापारीकरण किया जा रहा है। अंशदान के रूप में वेतन से पैसे काटकर पेन्शन देने की स्कीम शुरू की गई है। स्थायी कामों में भी ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नियुक्त श्रमशक्ति का 68 फीसद कैज्यूअल यानी या अस्थाई मजदूर–कर्मचारी हैं जिनसे कम तनख्वाह पर काम लिया जाता है और नियमित या पक्का नहीं किया जाता है। इन्हें मालिक मनमर्जी से जब चाहे हटा देते हैं। दिहाड़ी मार लेते हैं। इन्हें घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जाता है। सन 1886 में मजदूरों का जितना शोषण किया जाता था आज उससे भी कहीं ज्यादा शोषण है। भले ही यहाँ 8 घण्टे के कार्य दिवस को कानूनी मान्यता मिल चुकी है लेकिन देश–प्रदेश के ज्यादातर उद्योगों व कारखानों में 8 घण्टे का कार्य–दिवस, न्यूनतम वेतन, वेज स्लिप, हाजरी कार्ड, हाजरी रजिस्टर, ई.एस.आई. व पी.एफ. जैसे अनिवार्य कानूनी प्रावधान लागू नहीं हैं। मजदूरों की हालत बन्धुआ गुलामों से भी बदतर है। आंगनवाड़ी वर्कर–हैल्पर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और ग्रामीण चौकीदार सरकारी काम करते हैं फिर भी सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने को तैयार नहीं है। भवन निर्माण कारीगर–मजदूर–मिस्त्रियों के बोर्ड में पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद जटिल है। बहुत से श्रमिक पंजीकृत ही नहीं हैं अत: बोर्ड से मिलने वाले हितलाभों से वंचित हैं। पंजीकरण व हितलाभ पाने सम्बन्धी बहुत सारी बेजा शर्तें थोंपी हुई हैं। श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यूनियन बनाने व हड़ताल करने के बड़े संघर्षों से हासिल जनतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। चौतरफा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। शिक्षा व इलाज बेहद महंगा होता जा रहा है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक समस्याएं घनघोर हो उठी हैं। लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है।

मुक्ति का रास्ता

इन असहनीय और दमघोंटू हालात के खिलाफ जोरदार मजदूर आन्दोलन खड़ा करना ही बचने का एकमात्र रास्ता है। लोग अपनी रोजी–रोटी बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल भी हुई। लेकिन इस युग के महान मार्क्सवादी चिंतक सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष ने यह सीख दी है कि सही क्रान्तिकारी नेतृत्व के बिना महज स्वत:स्फूर्त विक्षोभ फूट पड़ने से ही समाज में क्रांतिकारी बदलाव नहीं आता है बल्कि उल्टे लोगों में निराशा–हताशा और राजनैतिक उदासीनता छा जाती है। समस्याओं से परेशान हो कर जब जनता में आन्दोलन की चाह पैदा होती है तो जनता में फूट डाल दी जाती है। हिन्दू–मुस्लिम, हिन्दू–सिख, हरियाणवी–बिहारी, गुजराती–मराठी का झगड़ा करा दिया जाता है। जबकि मजदूर पहले मजदूर है बाद में हिन्दू, मुसलमान, बंगाली, बिहारी या हरियाणवी है। मजदूर एकता व संगठन को मजबूत करते हुए, मजदूर आन्दोलन–जनान्दोलन करते हुए, जनकमेटियों–यूनियनों का निर्माण करते हुए जनता की राजनैतिक शक्ति को जन्म देते हुए जब राजसत्ता लोगों के हाथों में आएगी तब सही मायने में मुक्ति मिलेगी। मजदूर क्रान्ति के जरिये पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर शोषणहीन समाज कायम करना ही मजदूर आन्दोलन का ध्येय है। साम्यवाद केवल मजदूरों का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का सवाल है, मुक्ति का रास्ता है। मजदूर–कर्मचारी आन्दोलन को स्तर दर स्तर पूंजीवाद–विरोधी दिशा में आगे बढ़ाने के लिये जरूरी है कि पूंजीपतियों की ताबेदार उन तमाम पार्टियों, नेताओं और धोखेबाज संगठनों का पर्दाफाश किया जाए जो एक तरफ तो सत्ता में रहने के लिए पूंजीपतियों के स्वार्थ में जनविरोधी, मजदूर–विरोधी व दमनकारी नीतियों को लागू करते हैं और दूसरी तरफ उनके खिलाफ आन्दोलन करने का दिखावा करते हैं। मई दिवस का यह साफ सन्देश है। मई दिवस पूंजीपति वर्ग की अनिवार्य हार की पूर्वशर्त मजदूर आन्दोलन से इन संशोधनवादी विश्वासघातियों को अलग–थलग कर पूर्ण मुक्ति पाने के अपने ऐतिहासिक लक्ष्य की ओर लाल परचम फहराते हुए आगे बढ़ते जाने के अपने ऐतिहासिक ध्येय की याद मजदूर वर्ग को दिलाता रहेगा। मई दिवस आज हमें आन्दोलन की एक नई लहर खड़ी करने के लिए ललकार रहा है। आइये, इसका हम दृढ़ संकल्प लें!

शहीद भगत सिंह ने भेजा था लेनिन दिवस पर संदेश

24 जनवरी, 1930! लेनिन मृत्यु वार्षिकी के अवसर पर लाहौर षड्यंत्र केस के सभी अभियुक्त अदालत में लाल रूमाल बांध कर उपस्थित हुए। वे काकोरी पर गाना गाते सुनाई दिये। जैसे ही मजिस्ट्रेट ने अपना आसन ग्रहण किया वे समाजवादी क्रान्ति जिन्दाबाद! और साम्राज्यवाद का नाश हो! के नारे लगाने लगे। इसके बाद भगत सिंह ने अदालत में तार का मजमून पढ़ा और मजिस्ट्रेट से इसे तीसरे इण्टरनेशनल के अध्यक्ष को भिजवाने का आग्रह किया। तार में लिखा था :

''लेनिन दिवस के अवसर पर हम उन सभी को हार्दिक अभिनन्दन भेजते हैं जो महान लेनिन के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। हम रूस द्वारा किए जा रहे महान प्रयोग की सफलता की कामना करते हैं। हम खुद को अन्तरराष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन से जोड़ना चाहते हैं। मजदूरों के राज की जीत हो! पूँजीवाद का नाश हो! साम्राज्यवाद मुर्दाबाद!''

लाहौर षड्यंत्र केस के सभी अभियुक्त

(ट्रिब्यून, लाहौर में 30 जनवरी, 1930 को प्रकाशित)

आगामी लोकसभा चुनाव में

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवारों को वोट दें

चुनाव चिन्ह गिलास

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. सत्यवान द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग. नई दिल्ली–5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी–70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली–35 से मुद्रित। दूरभाष : 011–25726631, Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com